Horo, Shri N. E.

Jha, Shri Bhogendra

Khan, Shri Ghulam Mohammad

Lawrence, Shri M. M.

Masudal Hossain, Shri Syed

Mehta, Prof. Ajit Kumar

Mukherjee, Shri Samar

Rajda, Shri Ratansinh

Roy, Shri A. K.

Roy, Dr. Saradish

Saha, Shri Ajit Kumar

Shakya, Shri Daya Ram

Shastri, Shri Ramavatar

Shejwalkar, Shri N. K.

Tirkey, Shri Pius

Unnikrishnan, Shri K. P.

Varma, Shri Ravindra

Verma, Shri R. L. P.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Subject to correction, the result** of the division is :

AYES : 90

NOES : 29

The motion was adopted.

18.26 hrs.

ASSAM APPROPRIATION (NO. 2) BILL 1982**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA) : I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1982-83.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1982-83.

The motion was adopted.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA : I introduce* the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now Mr. Sisodia.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA : I beg to move.*

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1982-83, be taken into consideration."

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1982-83, be taken into consideration."

Now Prof. Ajit Kumar Mehta. Only 2 or 3 minutes.

(Interruptions)

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं कही हुई बात को दोहराना नहीं चाहता । अभी अभी गृह मंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही और चुनाव की एक प्रकार से घोषणा ही कर दी कि मार्च के पहले चुनाव होंगे। मैं इस का स्वागत करता हूं।

**The following Members also recorded their votes :

AYES : Sarvashri Narayan Datt Tiwari and Saminuddin.

**Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2 dated 5-8-1982.

*Introduced/Moved with the recommendation of the President.

विदेशियों के मामले में भी काफी बातें कही जा चुकी हैं और इस के बारे में और कुछ अधिक कहने की गुंजाइश नहीं है। केवल एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं। वहां एक विचित्र स्थिति है कि अभी भी वहां पर न विधान सभा में जन-प्रतिनिधि हैं और न ही इस संसद में असम के अधिकांश भागों के जन प्रतिनिधि हैं। नतीजा क्या है कि वहां एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि वहां के लोगों पर दूसरी जगह के लोग शासन कर रहे हैं। मैं एक बात आप को याद दिला दूं कि 100 साल पहले अमेरिका में जब ऐसी स्थिति आई कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जब उन के लिए विधान तैयार किया, तो वहां के लोगों ने इस बात का विद्रोह किया कि जिस पार्लियामेंट में हमारा एक प्रतिनिधि भी नहीं है, उन को हमारे लिए विधान बनाने का अधिकार नहीं है। तो इस परिपेक्ष्य में गृह मंत्री ने जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है।

विदेशियों के मामले में जितनी बातें कही गई हैं, वे काफी हैं लेकिन उन में एक बात मैं यह जोड़ देना चाहता हूं कि हमको याद रखना चाहिए कि विदेशियों का सवाल अकेले आसाम का सवाल नहीं है, यह पूरे राष्ट्र का सवाल है। इसलिए वहां पर विदेशियों के कारण अगर उस को इतना भार वहन करना है, तो वह सारा भार आसाम के ऊपर न डाल कर उस भार को सारे राष्ट्र को वहन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं और वे बड़े चतुर रहे हैं। उन्होंने जो अभी-अभी आंकड़े दिये हैं, उन आंकड़ों से यह सिद्ध किया है कि आसाम की आर्थिक रूप से उपेक्षा नहीं हो रही है।

MR. DEPUTY SPEAKER: You are on the Appropriation Bill. Where does the Home Minister come in?

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: But I must make my point.

उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खाली आंकड़ों से सिद्ध करने से काम नहीं चलेगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कुनबा नदी पार कर रहा था। उस परिवार के मुखिया ने नदी की गहराई की एवरेज निकाल कर अपने परिवार को नदी पार करने के लिए कहा जिसमें कि बच्चे भी थे और बड़े भी थे। उसने एवरेज निकाल लिया कि एक फुट गहरा पानी है मगर गहराई में पहुंच कर उसका सारा कुनबा डूब गया। इसलिए अगर आप आंकड़ों से कुछ सिद्ध करना चाहेंगे तो बात नहीं बनने वाली है।

मैं आपको आपके बजट से कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। आपने इस में गेस्ट हाउसिज और गवर्नमेंट होस्टल के लिए 27-3-82 को 16 लाख, 36 हजार रुपये रखे थे। अब आपने बढ़ाकर यह राशि 23 लाख 77 हजार कर दी है। इसका अर्थ है कि आप अनुत्पादक कार्यों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। इस से क्या विकास संभव है?

आपने आर्टस और कल्चर पर 52 लाख 28 हजार रुपये रखे थे उसको घटा कर आपने 45 लाख 68 हजार रुपये कर दिये है। आवास योजनाओं के लिए, जो कि जन कल्याण की योजनाए हैं उनके लिए आपने 1 करोड़, 26 लाख 72 हजार रुपये से घटा कर 1 करोड़ 14 लाख 74 हजार रुपये कर दिये। श्रम, रोजगार के लिए आवश्यकता होती है कि आवंटन को बढ़ाया जाए, उसके लिए आप उतनी ही राशि रखे हैं अर्थात पहले आपने 1 करोड़, 39 लाख 84 हजार रुपये की राशि रखी थी, अब उसके लिए 1 करोड़, 39 लाख, 83 हजार रुपये की राशि कर दी है। इसी प्रकार नशाबंदी के लिए आपने 25 लाख 18 हजार रुपये को घटा कर 25 लाख 17 हजार कर दिया है। इसी प्रकार बाढ़ के कारण जो भारी क्षति होती है, उसके नियंत्रण के लिए आपको ज्यादा राशि देनी चाहिए थी लेकिन आपने भूमि और जल संरक्षण कार्यों के लिए 1 करोड़ 95 लाख, 74 हजार रुपये की राशि को घटा कर 1 करोड़, 71 लाख 23 हजार कर दिया है। यहां पर आपको आवंटन बढ़ाना चाहिए था क्योंकि यह केवल असम का ही सवाल नहीं है, असम के निचले भागों का भी इस में हित निहित है। इसको आप घटा रहे हैं।

इसी प्रकार छोटे उद्योग धंधों के लिए जैसे कि सेरीकल्चर और वीविंग है, इनके लिए आपको

प्रोत्साहन देना चाहिए था। यहां पर भी आपने 2 करोड़, 32 लाख 33 हजार रुपये से घटा कर 2 करोड़ 27 लाख, 53 हजार कर दिया है।

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम की यातायात व्यवस्था अभी तक सुचारू नहीं है। उसके लिए, आपने थोड़ी ही रकम बढ़ाई है। 13 करोड़ 78 लाख से 14 करोड़ 62 लाख 17 हजार किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आपको और अधिक ध्यान देना चाहिए

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन मुद्दों पर ध्यान देते हुए ऐसे प्रबंध कर लें जिनसे आसाम का सचमुच में विकास हो। केवल बहानेबाजी न कीजिए कि वहां एस्टेबिलिटी नहीं रही इसलिए विकास रुका रहा। 1977 तक तो एस्टेबिलिटी रही।

इन सब बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सुनने का धीरज दिखाया।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के संबंध में चार मांगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Any discussion must be over with a speech by Shri Ramavatar Shastri. The last speaker on the other day on drought situation was Shri Ramavatar Shastri and we had good rains.

श्री रामावतार शास्त्री You helped me, Sir. मांग नम्बर 46 जिसका संबंध स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से है। आसाम में जिस सरकार ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का निर्णय लिया था, उसको मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहूंगा---- (व्यवधान) मैं यह जानना चाहूंगा कि वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, आपने क्या क्या सहूलियतें दी हैं। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अधिकांश बूढ़े हो चुके हैं। उनको अधिक से अधिक सहूलियत देने की आवश्यकता है, ताकि वे ज्यादा समय तक जिन्दा रह सकें।

दूसरी बात शिक्षा के संबंध में है। मैंने पहले भी यह सवाल उठाया था कि आसाम के सैकड़ों छात्र आंदोलन की वजह से और आगे की पढ़ाई की वजह से दिल्ली आ गए हैं लेकिन उनको एडमीशन नहीं मिल रहा है। मैंने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया था, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि कई छात्र और छात्राएं उनसे भी मिले हैं। इसलिए उनके लिए ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे यह न महसूस करें कि उनके यहां आंदोलन है, शिक्षा में व्यवधान है, इसलिए यहां की सरकार उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देती।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में पृथकतावादी आंदोलन के विरोधी छात्र भी हैं। सेक्यूलरिज्म में विश्वास करने वाले छात्र भी हैं, ऐसे जो लोग हैं ए आई एस एफ, एस एफ आई में, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना, चाहिए, ताकि पृथकतावादी तत्वों के खिलाफ ये लड़ सकें और एकता की भावना छात्रों में बढ़ सके।

चौथी बात सिविल सप्लाईज के बारे में है जो मांग नम्बर 41 से सम्बन्ध रखती है। आपने होगा कि देश की राशन की दुकानों में बहुत जगह राशन नहीं है। हम लोग जब सुखाड़ के सिलसिले में बहस कर रहे थे तब भी यह बात आई थी। अखबारों में आ रहा है कि असम में भी यह समस्या है। सिविल सप्लाईज विभाग का यह कर्तव्य है कि वहां जो वर्तमान स्थिति है इसको देखते हुए विशेष रूप से राशन की दुकानों में राशन की सप्लाई में किसी भी प्रकार की कमी न आने दे, नहीं तो एक तरफ आन्दोलन की मार से, पृथकतावादियों के दुष्कर्मों की शिकार वहां की जनता है और दूसरी तरफ आपकी मार की भी वह शिकार होगी। राशन की दुकानों में जो चीजें आप देते हैं वे पूरी-पूरी दें

प्राकृतिक विपत्तियों की चर्चा भी मंत्री महोदय ने की है। असम में बाढ़ आई और तूफान भी आया, एक साथ दो दो विपत्तियां बाढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी में और साइक्लोन भी आया गवालपाड़ा और शिवसागर जिले बुरी तरह से इस

वजह से क्षतिग्रस्त हैं। 18 आदमी बाढ़ में मर चुके हैं। यह अखबारों में आया है। हो सकता है इससे भी अधिक की मृत्यु हुई हो। उनकी मदद के लिए रिलीफ वर्क में, सहायता कार्यों में किसी भी प्रकार की सुस्ती नहीं होनी चाहिये। उनकी ज्यादा से ज्यादा सहायता आप करें ताकि उनकी जान भी बच सके और वे जिन्दा भी रह सकें।

यही चार मुद्दे थे जो मैं उठाना चाहता था। मगर गवर्नमेंट स्थिति बता सकती हो तो बता दे ताकि देश को मालूम हो कि आप क्या कर रहे हैं।

SHRI SAWAI SINGH SISODIA : Two hon. Members have participated in this Debate. I do not want to take more time of the House. But it is necessary to place the facts and figures before the House, so that the actual situation is understood properly.

In spite of political instability in Assam, the Central Government has been quite anxious, alert and has taken all the necessary steps for the economic development of Assam. The figures will show that while the total plan outlay for five years from 1974 to 1979 was Rs. 460 crores, the size of the Sixth Plan has been fixed at Rs. 1115 crores. The Central assistance has been fixed at Rs. 827 crores, which constitutes about 75 per cent of the entire Plan outlay. The per capita outlay for the Sixth Plan comes to Rs. 764 on the basis of 1971 Census. In the Fifth Plan the per capita Central assistance for all States was Rs. 102 while for Assam it was Rs. 166. In the Sixth Plan the per capita Central assistance to all the States is Rs. 258, while for Assam it is Rs. 565.

Regarding economic activities I want to place a few figures before the House. In power in 1980-81, 1981-82 and 1982-83 the amount allotted was Rs. 74.80 crores, Rs. 77.47 crores and Rs. 90.70 crores respectively. For agriculture and allied services the figures are Rs. 37.97 crores, Rs. 45.94 crores and Rs. 52.87 crores.

In all these sectors the amount has been increased and care has been taken for the wholesale economic development of Assam.

The amount allotted for major and medium irrigation is Rs. 9.75 crores, Rs. 10.80 crores and Rs. 10.80 crores in 1980-81, 1981-82 and 1982-83.

Many hon. Members have referred to roads and bridges. For Roads and Bridges the outlay in 1980-81 was Rs. 14.79 crores and in 1982-83 Rs. 16.50 crores. Similarly, for Industry and Minerals, the outlay in 1980-81 was Rs. 6.19 crores and in 1982-83 Rs. 10.75 crores. For Social and Community Services the corresponding figures are Rs. 42.95 crores and Rs. 42.47 crores. For Co-operation the amount increased from Rs. 3.88 crores to Rs. 5 crores during the corresponding period.

Many hon. Members have referred to the construction of the bridges over Brahmaputra. The Saraighat bridge is in existence since 1962. Another bridge, Bhomoraguri bridge near Silghat is under construction. A third bridge. Jogighopa bridge, has just now been approved.

Then the provision for flood relief has been increased from Rs. 3.46 crores to Rs. 5.46 crores in the regular budget.

For Roads the Plan outlay has been continuously increasing every year. In 1980-81 it was Rs. 14.79 crores; in 1981-82 it was Rs. 16 crores and in 1982-83 it was increased to Rs. 16.50 crores. The North Eastern Council will provide Rs. 2.23 crores for important inter-State roads.

Coming to the three points raised by Shri Ramavatar Shastri, education will take time. So far as the supply of essential commodities is concerned, every step will be taken to see that there is no part of the country which is not supplied food and essential commodities. The essential commodities are being supplied through the fair price shops. So, there is no cause for alarm or anxiety on that score. So, far as the freedom fighters are concerned,

the Central Government have taken all the precautions. Every possible help is being given to the freedom fighters by the Assam Government.

MR. Deputy SPEAKER The question is

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sum from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1982-83, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up clause by clause consideration of the Bill. . The question is

"That clauses 2, 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA I beg to move :

"That the Bill be passed".

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

18.49 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 6th August, 1982/*Sravana* 15, 1904 (*Saka*).